International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 02(II), April- June, 2026, pp. 185-189

वैश्विक संघर्षों के कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

डॉ. जलेंद्र कुमार शर्मा*

सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

*Corresponding Author: jkdausa77@gmail.com

Citation: शर्मा, जलेंद्र (2026). वैश्विक संघर्षों के कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(02(II)), 185–189. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.2(II).9116

सार

वैश्विक संघर्षों (जैसे पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के संकट) के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ जाता है। साथ ही, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर में निवेश करते है। इन कारणों से डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपया लगातार कमजोर हो रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं संस्थागत निवेश घट रहा ळे जो संस्थागत विकास को अवरूद्व करता है। रूपया के कमजोर होने के कारण आयात मंहगे हो जाते है, जिससे घरेलू बाजार में मंहगाई बढ़ जाती है।

शब्दकोशः *रूपये का अवभूतयन, वैश्विक संघर्ष, कन्या तेल संकट, पूंजी निकासी, व्यापार घाटा।*

प्रस्तावना

वैश्विक भू.राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों ने हमेशा से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को प्रभावित किया है। वर्ष 2025 और 2026 के दौरान दुनिया भर में हुए विभिन्न सैन्य और कूटनीतिक टकरावों के कारण भारतीय रुपये (INR) के मूल्य में अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। मार्च 2025 में जो रुपया प्रति डॉलर लगभग ₹85.53 के स्तर पर थाए वह मई 2026 तक ₹95 से ₹96 के रिकॉर्ड निचले स्तर को पार कर गया।

यह विस्तृत विश्लेषण इस बात की पड़ताल करता है कि वैश्विक संघर्ष किस प्रकार भारतीय रुपये के अवमूल्यन (Depreciation) का कारण बनते हैं और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

- **विनिमय दर और रुपये के अवमूल्यन का अर्थ**

साधारण शब्दों में रुपये के अवमूल्यन का अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा की क्रय शक्ति (Purchasing Power) अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम हो गई है। यदि पहले 1 डॉलर खरीदने के लिए ₹ 85 देने पड़ते थे, और अब उसी 1 डॉलर के लिए ₹ 96 देने पड़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि रुपया

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

कमजोर हुआ है और डॉलर मजबूत। यह उतार–चढ़ाव मुख्य रूप से वैश्विक बाजार में डॉलर की मांग और आपूर्ति (Demand and Supply) के संतुलन पर निर्भर करता है।

- **वैश्विक संघर्ष और रुपये में गिरावट के मुख्य कारण**

2026 में रुपये की इस तीव्र गिरावट के पीछे कोई एक घरेलू कारण नहीं हैए बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपजे कई संकटों का एक संयुक्त परिणाम है।

पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का व्यवधान

2026 के शुरुआती महीनों में पश्चिम एशिया विशेष रूप से इजराइल ईरान और अमेरिका के बीच में सैन्य टकराव चरम पर पहुंच गया। इस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे संवेदनशील मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य बाधित हो गया। विश्व का लगभग 20–30 प्रतिशत कच्चा तेल इसी मार्ग से गुजरता है। इस नाकेबंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude Oil) की कीमतें महज एक सप्ताह के भीतर $ 80 प्रति बैरल से उछलकर $111 $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में यह उछाल रुपये के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII/FPI) द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी की निकासी

जब भी दुनिया में युद्ध या अनिश्चितता का माहौल होता हैए तो वैश्विक निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों (Emerging Markets) से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं। इसे अर्थशास्त्र में (Flight to Safety) कहा जाता है। वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय शेयर और बांड बाजारों से लगभग ₹3.33 लाख करोड़ ($17 $18 बिलियन) से अधिक की निकासी की। जब ये निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं, तो वे अपने शेयरों को रुपये में बेचते हैं और उसे डॉलर में बदलकर बाहर ले जाते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है और रुपया तेजी से टूटता है।

अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मजबूती (Strong Dollar Index)

भू.राजनीतिक तनाव के समय अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सबसे सुरक्षित मुद्रा (Safe-Haven Asset) माना जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों को उच्च स्तर (4.43%) पर बनाए रखने के कारण दुनिया भर का धन अमेरिका की ओर आकर्षित हो रहा है। इसके विपरीत, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा घरेलू विकास को गति देने के लिए दिसंबर 2025 में रेपो रेट घटाकर 5.25% करने से दोनों देशों के बीच यील्ड एडवांटेजश् (ब्याज दर का अंतरद्ध कम हो गया, जिसने रुपये पर अतिरिक्त दबाव बनाया।

वैश्विक व्यापार और अमेरिकी टैरिफ नीति

2025–2026 में अमेरिका की नई संरक्षणवादी नीतियों और भारतीय वस्तुओं (जैसे रत्न, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स) पर लगाए गए 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के टैरिफ ने भारतीय निर्यात को प्रभावित किया है। इससे देश में आने वाले डॉलर की आवक कम हो गई, जिससे रुपये की स्थिति और कमजोर हुई।

- **वैश्विक संघर्ष से रुपया अवमूल्यन की प्रक्रिया (Transmission Mechanism)**

यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि विदेशों में होने वाला युद्ध भारत की घरेलू मुद्रा को किस क्रमबद्ध प्रक्रिया के तहत प्रभावित करता हैं।

- **चरण 1: वैश्विक संघर्ष की शुरुआत** – पश्चिम एशिया या यूरोप में युद्ध छिड़ने से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बनता है।

- **चरण 2 : जिंसों और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि –** तेल उत्पादक क्षेत्रों में तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल पार कर जाता है, जिससे भारत का आयात बिल अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है।
- **चरण 3 : डॉलर की मांग में उछाल –** महंगे तेल का भुगतान करने के लिए भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं।
- **चरण 4 : पूंजी का पलायन (Capital Flight)** – विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारतीय शेयर बाजार से निवेश वापस खींचते हैं और रुपये को डॉलर में परिवर्तित कर अमेरिका ले जाते हैं।
- **चरण 5 : रुपये का ऐतिहासिक अवमूल्यन –** बाजार में डॉलर की अत्यधिक मांग और रुपये की प्रचुर आपूर्ति के कारण विनिमय दर गिरकर ₹95 – ₹96 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच जाती है।

- **रुपये के अवमूल्यन का प्रक्षेपवक्र (2025-2026)**

नीचे दी गई तालिका स्पष्ट करती है कि पिछले एक वर्ष में वैश्विक घटनाओं के साथ.साथ रुपये का मूल्य किस प्रकार परिवर्तित हुआ है।

कालखंड/अवधि	विनिमय दर (USD/INR)	मुख्य वैश्विक एवं घरेलू घटनाक्रम	स्थिति
मार्च 2025	₹85.53	आधार स्तर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नीतिगत बदलावों की सुगबुगाहट।	स्थिर
दिसंबर 2025	₹90.10	इतिहास में पहली बार रुपये ने ₹90 का स्तर पार किया, अमेरिकी टैरिफ की घोषणा।	मध्यम गिरावट
मार्च 2026	₹94.71	पश्चिम एशिया (इजराइल–इरान) संघर्ष तेज हुआ थ्प् की रिकॉर्ड बिकवाली।	तीव्र गिरावट

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

- **नकारात्मक प्रभाव (Negative Impacts)**
  - **आयातित मुद्रा स्फीति (Imported Inflation) :** भारत अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं (कच्चा तेल, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और मशीनरी) आयात करता है। रुपये के कमजोर होने से इन सभी वस्तुओं का आयात महंगा हो जाता है। उदाहरण के लिए तेल कंपनियों को समान मात्रा में तेल खरीदने के लिए अब अधिक रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके कारण देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ती हैं और माल ढुलाई महंगी होने से आम उपभोक्ता वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं।
  - **चालू खाता घाटे (Current Account Deficit - CAD) का बढ़ना :** जब देश का कुल आयात बिल उसके कुल निर्यात राजस्व से अधिक हो जाता है, तो चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ जाता हैं–तेल की उच्च कीमतों और कमजोर रुपये के कारण 2026 में भारत का CAD अनुमान से $40 से $50 बिलियन अधिक विस्तृत हो गया है।
  - **विदेशी ऋण का बढ़ता बोझ (External Debt Burden):** भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियों ने विदेशों से भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर में ऋण (ECBs) ले रखा है। यदि किसी कंपनी ने ₹85 के स्तर पर $10 लाख का कर्ज लिया था (अर्थात ₹8.5 करोड़), तो अब ₹96 के स्तर पर, उसी $10 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी को ₹9.6 करोड़ देने होंगे। ऋण बोझ बिना किसी अतिरिक्त पूंजी के ही बढ़ गया है।

- **विदेशी शिक्षा और पर्यटन का महंगा होना :** मध्यम वर्ग के जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप जा रहे हैंए उनकी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च अचानक 10.12 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसी तरह, भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राएं खर्चीली हो गई हैं।
- **ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में देरी :** जब रुपये का अवमूल्यन होता है, तो डॉलर के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ जाता है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, रुपये का विनिमय दर ₹95.96 से ऊपर बने रहने के कारण 5 ट्रिलियन डॉलर की उपलब्धि हासिल करने की समयसीमा आगे खिसककर वित्तीय वर्ष 2030 तक जा सकती है।

- **सकारात्मक प्रभाव (Positive Impacts)**
  - **निर्यात उन्मुख क्षेत्रों (Export Sectors) को बढ़ावा :** कमजोर रुपया भारतीय निर्यातकों के लिए वरदान साबित होता है। सूचना प्रौद्योगिकी (IT Services) जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो तथा फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल कंपनियों को डॉलर की मजबूती से अधिक रुपया राजस्व प्राप्त होता है जिससे उनका मुनाफा और वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ती है।
  - **घरेलू विनिर्माण और "आयात प्रतिस्थापन" (Import Substitution):** विदेशी वस्तुओं के महंगे होने के कारण घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं का रुझान स्थानीय उत्पादों की तरफ बढ़ता है। इससे 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं के तहत देश के भीतर ही विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है तथा आयात पर दीर्घकालिक निर्भरता घटती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार की सुधारात्मक रणनीतियाँ

- **विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिक्री (Spot Market Intervention):** आरबीआई ने अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का उपयोग करते हुए हाजिर बाजार में सक्रिय रूप से डॉलर बेचे हैं ताकि रुपये की गिरावट को नियंत्रित किया जा सके।
- **तरलता प्रबंधन और मुद्रा अदला–बदली (Currency Swaps):** केंद्रीय बैंक ने बाजार को स्थिरता प्रदान करने के लिए करेंसी स्वैप जैसे उपकरणों का उपयोग किया है ताकि नकदी संतुलन बना रहे।
- **सट्टेबाजी पर लगाम (Regulatory Tightening):** बैंकों के ओपन पोजीशन की सीमा तय करके और नॉन–डेलिवरेबल फॉरवर्ड (NDF) बाजार में सट्टा गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
- **अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए विशेष योजनाएं :** सरकार और आरबीआई विदेशी प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए विशेष डिपॉजिट योजनाएं और सॉवरेन बांड्स शुरू कर रहे हैं।

निष्कर्ष और भविष्य की राह

2026 में भारतीय रुपये की गिरावट कोई आंतरिक आर्थिक संकट नहीं हैए बल्कि यह पूरी तरह से बाहरी और भू–राजनीतिक झटकों (External Shocks) के प्रति भारतीय बाजार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वैश्विक युद्धों और प्रतिबंधों के इस दौर में भारत की आर्थिक बुनियादी स्थिति अभी भी मजबूत है। लॉन्ग–टर्म में समाधान के लिए भारत को ऊर्जा विविधीकरण (रिन्यूएबल एनर्जी) बढ़ाना होगा, रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण (स्थानीय मुद्राओं में व्यापार) करना होगा और विनिर्माण निर्यात को मजबूत करना होगा ताकि किसी एकल वैश्विक मुद्रा पर निर्भरता सीमित की जा सके।

संदर्भ एवं स्रोत

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) - दैनिक विनिमय दरें एवं मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट (2025–2026) (स्रोतः rbi.org.in)

2. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार . मासिक व्यापार एवं निर्यात आंकड़े (स्रोतः commerce.gov.in)
3. फेडरल रिजर्व बैंक (US Federal Reserve) - वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता एवं ब्याज दर बुलेटिन (स्रोत : federalreserve.gov)
4. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) - वैश्विक तेल आपूर्ति एवं होर्मुज जलडमरूमध्य संकट विशेष रिपोर्ट (स्रोतः iea.org)
5. लाइवमिंट एवं बिजनेस स्टैंडर्ड – भारतीय वित्तीय बाजार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) प्रवाह रिपोर्ट (स्रोत: livemint.com/business-standard.com)

❑❑❑